राष्ट्रीय राजमार्ग-3 का निर्माण

***215. श्री राम जेठमलानी:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के निर्माण की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंप दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितनी राशि खर्च होने का अनुमाग है और विभिन्न राज्यों में कुल कितनी लम्बी सड़कों का निर्माण किया जाएगा;

(ग) परियोजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस परियोजना के निर्माण के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि यह आधुनिक तकनीक पूंजी प्रधान है, श्रम प्रधान नहीं; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजशेखर मूर्ति): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 3, जो आगरा से बम्बई तक जाता है, के निर्माण की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को नहीं सौंपी गई है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

Privatisation of Postal Delivery System in Andhra Pradesh

216. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government have any poposals to privatise postal delivery system in Andhra Pradesh;

(b) if so, the details of such proposals;

(c) whether it is a fact that unemployed youth have applied for permission to operate Branch Post Offices in Andhra Pradesh; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF THE STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) and (b) No, Sir.

(c) and (d) There is no scheme of permitting unemployed youth to operate branch post offices.

Crimes in Vasant Kunj and Hauz Khas Areas in New Delhi

217. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that thefts, burglaries and murders have shown an upward trend in the capital particularly in the jurisdiction of Hauz Khas and Vasant Kunj police stations;

(b) if so, break up of these figures, police posts and station wise;

(c) number of cases of theft and burglaries in these areas which are still unsolved; and

(d) what action is being taken in the rest of the cases of thefts and burglaries?

THE MINISTER OF THE STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (PROF. M. KAMSON): (a) and (b) The number of thefts, burglaries and murders reported in Delhi and in the jurisdiction of police stations Hauz Khas and Vasant Kunj during the period from 1.8.95 to 31.1.96 (month-wise) is given in the Annexure [*See* Appendix 176, Annexure No 10].

(c) The number of unsolved cases of theft and burglaries reported during the period from 1.8.95 to 31.1.96 in the areas

of police station Hauz Khas and Vasant Kunj is as under:

Crime	P.S. Hauz Khas	P.S. Vasant Kunj
Theft	137	98
Burglary	18	12

(d) The listed criminals and suspects are being throughly interrograted. Door to door survey has been conducted for the verification of domestic servants. Patrolling has been intensified in the area. The resients are being apprised with the security measures to the taken by them. Neighbourhood watch scheme has been started in these areas. Extra pickets are being laid during night hours in the crime infested areas.

बिहार के मधुबनी जिले में कार्यरथ प्लाइवुड कारखाने

*218. **श्री राम देव भंडारी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के मधुबन जिला में प्लाईवुड के कितने कारखाने कार्यरत हैं;

(ख) क्या उपरोक्त वर्णित कारखानों की संख्या इस जिले में वृक्षों की संख्या की तुलना में काफी ज्यादा है;

(ग) क्या इस कारखानों के कारण वृक्षों को बड़ी तेजी से काटा जा रहा है जिससे पर्यावरण प्रभावित हो रहा है; और

(घ) क्या सरकार इस मामले की शीघ्र जांच कराकर वृक्षों का कटाव रोकने के लिए बड़ी पैमाने पर कारखानों को बन्द करेगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

राजकोट में उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना

219. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजकोट में उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण एककों के विकास की व्यापक संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव): (क) जी नहीं।

(ख) स (ग) गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण एककों के विकास की संभावना है। खाध प्रसंस्करण उद्योग के निवेश को प्रोत्साहन देने के विचार से सरकार ने अपनी नीतियों को उदार बनाया है और अल्कोहल पेयों की किण्वन और आसवन, चीनी व लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंस-मुक्त कर दिया गया है। सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु विदेशी इक्विटी निवेश की अनुमति भी देती है। विदेशी प्रोद्यौगिकी करारों का उदारीकरण व खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए वित्तीय राहतों जैसे कई अन्य प्रोत्साहन पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं। मंत्रालय कुछ योजना स्कीमें भी चला रहा है जिनके तहत संयुक्त उद्यम, सहायता प्राप्त/सहकारी क्षेत्रों या निजी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण एककों को स्थापना/उन्नयन के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से प्राप्त हुए प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

गुजरात में प्रदूषण

220. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के प्रमुख शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसका जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन शहरों में प्रदूषण रोकने के लिए पहले से चलाई जा रही प्रदूषण नियंत्रण योजनाएं पर्याप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रदूषण को रोकने में अब तक कितनी सफलता मिली है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और